Indian J. Soc. & Pol. 04(03):2017 :123-128 **ISSN: 2348-0084(PRINT)**
Special Print Issue 2017 **UGC Journal List No 47956**

नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में गुजरात में विकास

राजेश भाटी[1]

[1]शोध छात्र, राजनीतिविज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

इतिहास साक्षी है, दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व किसी प्रांत और राज्य की प्रसिद्धी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, जबकि देश ही नहीं, समग्र विश्व, कडी प्रतिस्पर्धा के साथ विकास की यात्रा में निरंतर आगे बढ रहा हो। महान् उपलब्धियों और विकास के सर्वोच्च शिखर छूने के साथ–साथ, जहाँ वैश्विक स्तर पर नित नसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हों, तब ऐसे काँटे के मुकाबले के बीच छोटा सा प्रांत गुजरात दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करे, तो उसका श्रेय स्वाभाविक रूप से दूरदर्शी नेतृत्व को ही जाता है, गुजरात का यह सौभाग्य है कि उसे नरेन्द्र मोदी के रूप में केवल दूरदृष्टा व्यक्तित्व ही नहीं, अपितु कर्मठ, ईमानदार और समर्पित मार्गदर्शक मिला।

KEY WORDS: *विद्युत (ज्योतिग्राम योजना), कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, औद्योगिक विकास, अधोसंरचना, मानव संसाधन, आपदा प्रबंधन, शासन सुधार, मानव विकास सूचकांक*

परिचय

नरेन्द्र मोदी ने जब 7अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब गुजरात 26 जनवरी 2001 को भुज में आये भीषण भूकंप की विभीषिक से गुजर रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होने मुख्यमंत्री पद संभाला, भूकंप की विभीषिका का सामना करने के साथ उनके सामने सबसे बडी चुनौती प्रशासन में जन विश्वास की पुनर्स्थापना की थी।

विद्युत

ज्योतिग्राम योजना :–

''नरेन्द्र मोदी ने 2013 में ज्योतिग्राम योजना' शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण तथा बिना बाधा के बिजली आपूर्ति की गुणवता सुनिश्चित करना है। 'ज्योतिग्राम योजना' गुजरात के 18065 गाँवों में बिना कटौती के चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए बनाई गई थी। इसके लिए 1290 करोड़ रूपये आंवटित किए गए।

ज्योतिग्राम योजना की विशेषताएँ–

नए ट्रांसफार्मर–18,724

नए बिजली खंभे –17,28,344

नई हाई टेंशन लाइनें–56,307 किमी.

नई लोटेंशन लाईनें–22,146 किमी.

ऊर्जारक्षक :–

अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली का प्रयोग कैसे करें? बिजली के प्रयोग से कैसे बच सकते है? क्या हमें प्रयोग के बाद बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्या हमें पूरे समय एयर कंडीशनर की जरूरत होती है? क्या हमें लिफ्ट की जरूरत पड़नी चाहिए या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए? बिजली के बल्ब सही हैं या ट्यूबलाइट या सीएफएल?

अगर बच्चों को इस तरह की बुनियादी बातें सिखाई जाएं तो परिवार के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। नतीजन परिवार के सदस्यों और देशवासियों में बिजली बचाने की प्रवृति पैदा होगी इस अदभुद स्थिति हासिल करने के लिए गुजरात के सभी स्कूलों में ऊर्जा संरक्षकों की समितियाँ बनाई गयी इस कार्यक्रम का नाम बर्ड (बाल ऊर्जा रक्षक दल) रखा गया गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2004 में संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम शुरू किया।

नहर शीर्ष सौर ऊर्जा :–

गुजरात में अधिकतर स्थानों पर पानी की कमी थी क्योंकि वहाँ वाष्पन तेजी से होता है, और नहरों का पानी खेतों तक पहुँचने से पहले ही सूख जाता था। नरेन्द्र मोदी सरकार ने इसका एक अलग हटकर समाधान खोजा। उसने 2012 में नर्मदा नहर पर प्रयोग के तौर पर सिंचाई नहरों को फोटोबोल्टिक शीटों से ढकने की योजना तैयार की और 2012 कें मध्य तक 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन भी शुरू कर दिया।

पवन ऊर्जा :–

गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर पवन की समृद्ध क्षमता की पहचान की जहाँ से हवा से करीब 5000 मेगावाटबिजली बनाई जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए गुजरात ने 2007 में पवन ऊर्जा बनाने की नीति घोषित की। विभिन्न तरह की रियायतें देकर, बहुत ही कम अवधि में

1:Corresponding Author

2013 के आकँडों के अनुसार हवा से 3000 मेगावाटबिजली बनाई जा रही है।

ज्वारीय उर्जा :–

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने समुद्रीलहरों से बिजली बनाने की योजना भी शुरू की। 2011 में गुजरात में इस तरीके से 200 से 400मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रवधान किया गया। गैर–परम्परागत स्रोत से बिजली बनाने का यह भारत में नया प्रयास है।

रोशन गुजरात :–

जब 30 जुलाई 2012 को नेशनल ग्रिड फेल हो गया तो दिल्ली समेत 19 राज्यों में दो दिन के लिए एक तरह से अंधकार छा गया 120 करोड़ की आबादी में से करीब 60 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए दुनिया सोचनें लगी कि भारत सुपर– पावर कैसे बनेगा?

कृषि

जब शेष भारत भारी मुसीबतों से जूझ रहा है तब मोदी का गुजरात इन सबसे बचा हुआ है। हाँ यह हैरत की बात है कि गुजरात ने हर मोर्चे पर विशिष्ट उपलब्धियाँ हासिल की हैं। कृषि भी इसका उपवाद नहीं है।

विशिष्ट कृषि विकास :–

गुजरात विशाल रेगिस्तान और बंजर भूमि के लिए जाना जाता है। करीब 60% जमीन सूखी है और वर्षा की कमी से ग्रस्त है। ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच गुजरात ने कृषि के क्षेत्र में अद्भुद विकास हासिल किया है। पिछले दस वर्षों मे (2012 तक) उसकी औसत विकास दर 9.6% रही (इस अवधि में भारत की विकास दर 3.5 % रही)। 21वीं सदी के पहले दशक में गुजरात में भू–जल स्तर में बहुत अधिक, 8 फीट तक की वृद्धि हुई।

बंजर भूमि में खेती :–

वर्ष 2000 से पहले सौराष्ट्र जैसे बंजर क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती थी। और जो भी बारिश होती थी, उसका पानी समुद्र में बहकर बेकार हो जाता था। अब पूरा परिदृश्य बदल चुका है, पिछले दस सालों में गुजरात सरकार ने एक लाख से अधिक चैक डैम बनाए हैं। और पानी का भंडारण किया गया है। बहुत सारे तालाब और पोखर बनाने से बंजर भूमि कृषि योग्य उपयोगी उपजाऊ भूमि में बदल गयी है। पिछले एक दशक में (2012 तक) लगभग 35 लाख हेक्टेयर नई जमीन को कृषि योग्य बनाया गया है।

पानी बचाओ– अधिक बूँदे अधिक उपज :–

मोदी ने 'एक बूँद पानी भी बेकार मत करों' का नारा देकर लोगों को प्रेरित किया उन्होने लोगों के मन में विश्वस पैदा किया कि सौराष्ट्र क्षेत्र और उत्तरी गुजरात के जिलों की बंजर भूमि भी खेती के लिए उपयोगी हो सकती है। उन्होने वर्षा के पानी को रोकने तथा इसे इकट्टा करने के अनेक उपाय किए। उन्होनें इसके लिए हर संभव प्रयास किए।

बांध निर्माण :–

वर्ष 2000 तक गुजरात में मात्र 10000 चेक डैम थे, लेकिन 2008 के अंत तक इनकी संख्या 1.13 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त 2.40 लाख तालाब भी खासतौर पर खेती के लिए तैयार किए गए। गुजरात में हर सार औसतन 5000 नए चैक डैम बनाए जा रहे हैं।

नदियों को जोड़ना :–

भारत में नदियों को जोड़ने की बात तो होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालाँकी नरेन्द्र मोदी ने बिना कुछ कहे इस पर अमल कर दिखाया। मोदी ने 17 बंजर और सूखी नदियों को नर्मदा नदी से जोड़ा और उन्हें स्थायी जलस्रोत बना डाला।

ड्रिप सिंचाई :–

''आमतौर पर किसानों को खेती में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि पहले से तंगी में फँसे अधिकतर किसान इसे अपनाने से बचते हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनकी इस समस्या को समझा और 2005 में किसानों की सहायता के लिए एक एजेंसी– गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड' (जी जी आर सी एल) गठित की। इस काम के लिए खास तौर पर 1500 करोड़ रूपये आंवटित किए गए।

कृषि विश्वविद्यालय :–

नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय का। उन्होंने इनकी संख्या बढाकर चार की और खास बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों में से हर ऐक को विशेषज्ञता का क्षेत्र चुनने का निर्देश दिया गया तथा गहन शोध करने की सलाह दी गई।

पशुगृह :–

जानवरों के लिए पशु गृह स्थापित करने का विचार सर्वप्रथम गुजरात में अपनाया गया। मोदी ने 2011 में गुजरात के साबरकांठा जिले के अकोदरा गाँव में इस तरह के पहले पशु–गृह का उद्घाटन उद्पास किया था। इस पशु–गृह में करीब 250 परिवारों के लगभग 1000 जानवर रहते हैं।

कृषि आय :–

नरेन्द्र मोदी सरकार के कृषि पर अधिक ध्यान देने के परिणाम स्वरूप शुद्ध कृषि आय 9000 करोड़ रूपये से बढकर स्थिर मूल्यों पर 46,379 करोड़ रूपये हो गई और वर्तमान मूल्यों (2010–11) पर 96, 862 करोड़ रूपए हो गई। दुग्ध उत्पादन और इसके निर्यात में भारत विश्व की अग्रिम पंक्ति में हमेंशा रहा है। इसका प्राथमिक कारण गुजरात ही है। नरेन्द्र मोदी के कार्यराल में गुजरात में औसत विकास दर 75 प्रतिशत पर स्थिर रही है।

शिक्षा

किसी राज्य के विकास का पैमाना वहाँ की साक्षरता दर होती है। गुजरात में बालिका साक्षरता दर 2001 में मात्र 57.8 प्रतिशत थी, लेकिन एक दशक में यह आश्चर्यजनक रूप से लगभग 13 प्रतिशत बढकर 70.5 प्रतिशत हो गयी। मोदी की विभिन्न योजनाओं ने राज्य को महिला शिक्षा तथा समूचे शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता की है।

शिक्षा–महोत्सव :–

मोदी सरकार विद्यालय खुलने पर स्कूली बच्चों को सुखद अनुभव का अहसास कराना चाहती थी, अतः स्कूल खुलने के पहले दिन को बड़े पैमाने पर यादगार बनाने के लिये समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसे शाला प्रवेश–महोत्सव' का नाम दिया गया। इस महोत्सव में स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों के नाम स्कूल में लिखवाने के सारे प्रयास किए गये और सुनिश्चित किया गया कि कोई बच्चा स्कूल जाना न छोड़े। इस महोत्सव के दौरान बच्चों का स्कूल में कापियाँ और बैग देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं भी उपस्थित होकर इस समारोह में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते थे। 2013 में हुए 12 वे महोत्सव में मोदी ने गाँधी नगर जिले के लिखोड़ा गाँव में जाकर अभिभावकों को बच्चों को, स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।

बालिका शिक्षा के लिए कन्या केलावणी योजना :–

राज्य में बालिका शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए मोदी सरकार ने कन्या केलावनी आंदोलन प्रारम्भ किया। 2003 में यह आंदोलन 100 प्रतिशत लड़कियों के नाम स्कूल में दर्ज कराने के बडे उद्देश्य के साथ शुरू हुआ। 2003–04 में बालिकाओं के दाखिले 75 प्रतिशत थें, लेकिन पाँच वर्ष के अंदर 2008–09 तक यह 23 प्रतिशत बढकर 98 प्रतिशत हो गए। 'महिला साक्षरता व शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कन्या केलवणी योजना'

(कन्या शिक्षा अभियान) महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

विद्यालय गुणवत्ता का अंकेक्षण (आंडिट) :–

2009 में मोदी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता की स्थिति की जाँच करने के लिए गुणोत्सव आंदोलन की शुरूआत की । नरेन्द्र मोदी ने लगभग 3000 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इस आंदोलन में लगाया। प्रत्येक वर्ष वे राज्य भर के 32,274 प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता की जाँच करते है। इस आंदोलन की निगरानी और उसके प्रभाव के आकलन के लिए एक अन्य पक्ष तैनात किया गया है, जो समय–समय पर सुधार के लिए सिफारशें करता है।

नए विश्वविद्यालय :–

2001 में गुजरात में मात्र 11 विश्वविद्यालय थे, जोकि 10 सालों में ही बढ़कर 41 हो गए। मोदी सरकार ने 'रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' और फोरेंसिक साइंस युनिवर्सिटी स्थापित करके कुछ रचनात्मक कदम उठाए। मोदी ने 2013 में देश का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया।

अंग्रेजी प्रशिक्षण :–

कैंब्रिज विश्वीवद्यालय के सहयोग से गुजरात ने 2007 में अपने राज्य के युवाओं में अंग्रेजी दक्षता बढाने के लिए एक संगठन–'सोसायटी फॉर द क्रिएशन ऑफ अपॉरच्यूनिटी फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश (स्कोप) की स्थापना की 2012 के अंत तक राज्य भर में 450 केन्द्र स्थापित हो चुके थे। 2013 के अंत तक इस कार्यक्रम से करीब 3,60000 युवा अंग्रेजी का प्रशिक्षण ले चुके थे। कालेज छात्र–छात्राओं की अंग्रेजी सुधारने के लिए 'डेल' (डी ई एल एल) डिजिटल इंग्लिश लैंग्वेज लैब का गठन किया गया। 2011 के अंत तक 217 कॉलेजों ने अपने 'डेल' स्थापित कर लिये थे।

कंप्यूटर ट्रेनिंग :–

मोदी के 'एम्पावर इलैक्ट्रॉनिक मैनपावर' कार्यक्रम में राज्य के युवाओं को कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दी जाती है, इसमें हर साल हर तालुके के करीब 1000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

बुक रींडिग क्लब :–

मोदी सरकार ने लागों में पुस्तकें पढने की आदत डालने के लिए एक बुक रीडिग क्लब 'वांचे गुजरात शुरू किया जो पुस्तकें पढने के लिए रूचि पैदा करता है। आई टी आई पास करने वाले छात्र पहले उन निजी और सरकारी नौकरियों के लिए अवेदन नहीं कर पाते थे, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता 12 वीं कक्षा थी, जबकि वे दसवी कक्षा के बाद 2 वर्ष की आईटीआई कर चुके थे। मोदी सरकार ने नियम बदलकर इस अड़चन को दूर किया और आईटीआई को 12 वीं के समकक्ष कर दिया। इससे आईटीआई के छात्रों को नौकरी के अधिक अवसर मिलने लगे।

प्रबंध शिक्षा :–

भारत का शीर्ष प्रबन्धन संस्थान– भारतीय प्रबन्धन संस्थान' अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। मोदी सरकार ने 150 करोड़ रूपये का आंवटन करके गांधीनगर में युवा उद्यमियों के लिए विश्वस्तरीय संस्थान–'आई क्रिएट' की स्थापना की। इंफोसिस के नारायणमूर्ति इस संस्थान को इसके उद्देश्य प्राप्त करने में प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं।

स्वास्थ्य

'इ–ममता' कार्यक्रम

मोदी सरकार ने सुरक्षित प्रसव के लिए 2010 में एक नवीन कार्यक्रम 'इ ममता' शुरू किया। यह कार्यक्रम पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित था। इस कार्यक्रम सेस्वास्थ्य अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के खान–पान के तरीकों पर निकटता से निगाह रखने और प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात जरूरी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिली ।

मातृ–वंदना योजन :

'मातृ–वंदना योजना' जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु है। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में रू॰ 23.80 करोड़ का प्रवधान है। इसके लिए गुजरात सरकार को पुरस्कार भी मिल चुका है।

चिरंजीवी योजना :–

गुजरात सरकार ने मातृत्व से संबन्धित सुविधाओं कों गरीबों तक पहुँचाने के लिए निजी अस्पतालों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था की। इसी सोच के नतीजे के रूप में चिरंजीवी योजना सामने आई। 2005 में इस कार्यक्रम को प्रयोग के तौर पर कुछ स्थानों पर लागू किया गया। नवीन एवं सफल क्रियान्वयन के लिए चिरंजीवी योजना को प्रतिष्ठित 'एशियन इनोवेसन' अवार्ड से सम्मानित किया गया।

पेयजल

हमारी पृथ्वी के 71 प्रतिशत हिस्से में पानी है, लेकिन उसका केवल एक प्रतिशत ही पीने योग्य है। उन्होने विशेषज्ञों से सलाह ली और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभावशाली जल प्रबंधन की कमी ही व्याप्त जल संकट का कारण है। इसके लिए उन्होने एक कार्ययोजना और 2001 में ही उठाए जाने वाले कदमों की प्राथमिकता सूची बनाई। योजना में मुख्य जोर जल्दी–से –जल्दी भू जल पर निर्भरता समाप्त करने पर दिया गया, जिसके लिए वर्षा के जल और नदी जल के प्रयोग के लिए विस्तृत पैमाने पर अघोसंरचना तैयार की गई।

नर्मदा नहर :–

मोदी सरकार ने गुजरात की दक्षिण–पूर्व सीमा पर बहने वाली नर्मदा नदी के जल को पूरे गुजरात राज्य में पहुँचाने के लिए नहरों की खुदाई की योजना बनाई। इस योजना से 11000 से अधिक गाँवों और लगभग127 शहरों को पेयजल उपलब्ध. कराने में सहायता मिली।

जलनिकाय :–

जलनिकाय वास्तव में पानी को धरती के अंदर पहुँचाने में सहायक होते है, जिससे भूजल स्तर बना रहता है । इसके लिए मोदी सरकार ने झील, जलाशय और तालाब जैसे अनेक नए निकाय तैयार किए। पुराने जल निकायों की मरम्मत करके गहरा करके, सफाई करके उन्हें फिर से दुरूस्त किया गया और उनका विस्तार किया गया, ताकि उनमें और अधिक पानी आ सके 2005 से 2013 तक आठआलों में ही गुजरात सरकार ने 'एसपीपीडब्ल्यूसीपी प्रोजेक्ट' के द्वारा राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3,53 937 चेक डैम कई वाटर टैंक और अनेक तालाब विकसित किए हैं।

ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन समितियाँ :–

ग्राम स्तर पर पानी की जरूरते संभालने और जल संसाधनो की देखभाल के लिए मोदी सरकार ने ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन समितियों का गठंन किया फरवरी 2013 के अंत तक गुजरात के 18147 गाँवों में ये समितियाँ बन चुकी थी। प्रत्येक जल समिति के पाँच सदस्यों को सरकार ने पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिए प्रशिक्षण दिया। 2012 के अंत तक करीब 2,11, 575 लोगों को गुणवत्ता ऑडिट करने का प्रशिक्षण दिया गया। गाँव में पानी से संबंधित सभी मुद्दे हल करना इन समितियों का काम है।

रेनवाटर हार्वेस्टिंग :–

घरों के स्तर पर वर्षा के जल को बचाने और भू–जल स्तर बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने वाटर हार्वेस्टिग के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई और 72 प्रतिशत कवरेज के साथ गुजरात को देश में अग्रणी बना दिया; जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 17 प्रतिशत के दयनीय स्तर पर था। 'मोदी सरकार ने 65 लाख का वाटर हार्वेस्टिंग ढ़ाँचा तैयार किया।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विस्तार ब्यूरो–इंडेक्सटीबी :–

'इंडेक्सटीबी' गुजरात में सारे निवेशों के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करती है। यह संगठन राज्य में नए व्यापार को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। यह टीम विश्व स्तर पर जाकर गुजरात की शक्ति ओर उपलब्ध व्यापारिक अवसरों को प्रचारित करके उसे निवेश केन्द्र के रूप में प्रोत्साहित करती है। यह संगठन विश्व के उन औद्योगिक घरानों की पहचान करती है, जो गुजरात में

निवेश के इच्छुक है और उन्हे व्यापार संचालन करने के लिए सारी आवश्यक सहायता देकर उनका सहयोग करता है।

वृक्षों की संख्या में वृद्धि :–

मोदी सरकार ने वृक्षों की गणना का कार्यक्रम बनाया सभी शहरों एवं कस्बों को अपने बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा पौधे लगाने एवं हरियाली कायम रखने के लिए नियत करना आनिवार्य कर दिया। वन महोत्सव शहरी हरियाली योजना स्मृति वन, आक्सीजन पार्क, और हरियाली संरक्षण जैसी अनेक योजनाएँ गुजरात सरकार ने राज्य की हरियाली को बचाये रखने के लिए शुरू की। जिससे राज्य में वृक्षों की संख्या बढ़ती चली गयी।

सड़कें :–

अच्छी सड़कें भी किसी राज्य की अधोसंरचना का महत्वपूर्ण भाग हैं। मोदी सरकार ने सड़कों की योजना स्थानीय लोगों की भागीदारी से तैयार की। 1995–96 में सड़कों के लिए राज्य के बजट का 4.6 प्रतिशत हिस्सा (1300करोड़ रू) आवंटित किया गया था, लेकिन 2010–11 में मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 9.3 प्रतिशत (27,500 करोड़ रूपए) कर दिया जिससे राज्य में प्रभावशाली सड़कों का जाल बिछाया गया।

वायुयातायात में वृद्धि :–

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बढ़ा वायु यातायात इस बात का प्रमाण है कि मोदी के गुजरात में तीव्र विकास जगह ले रहा है। 1990 के मध्य में अहमदाबाद में उड़ानों की संख्या एक अंक में थी। 2012 में दिन भर में 100 से अधिक उड़ाने है, मार्च 2012 में ही करीब 3,492 उडानें अहमदाबाद हवाइ अड्डे से हुई। 2007–08 मे कुल 25 लाख यात्रियों ने अहमदाबाद हवाई अड्डे का उपयोग किया। 2012–13 में 41,62, 747 यात्रियों ने अहमदाबाद अवाई अड्डे का उपयोग किया था।

रोजगार सृजन :–

सरकारी रोजगार कार्यालयों के आंकडों के अनुसार 2007 में पूरे भारत में 2.64 लाख नौकरियों इनके माध्यम से पैदा हुईं। इनमें से 1.78 लाख यानी कुल नौकरियाँ का 67.42 प्रतिशत हिस्सा गुजरात में ही था। 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर 4.71 लाख नौकरियाँ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बनी, जिनमें गुजरात में 2.25 लाख यानी 47.85 प्रतिशत थी।

आपदा प्रबंधन

26 जनवरी 2001 को भारत के 52 वे गणतंत्र दिवस पर भारत में हाल के इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आया, जिससे लगभग 14000 लोगों की जानें गई, राज्य का 80 प्रतिशत हिस्सा, 21 जिलों में इसका प्रभाव पड़ा। सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाला शहर भुज था। छः से सात वर्षो में करीब 11 लाख मकान रहने लायक हो गए, जिनमें से करीब 2 लाख मकान नए बनाए गए थे, और बाकी की मरम्मत की गई थी।

निष्कर्ष

किसी भी राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र विकास के लिए अनवरत प्रयास करने पड़ते हैं। जो कि नरेन्द्र मोदी ने अपने 13 वर्षो के मुख्यमंत्री काल में गुजरात में किए। नरेन्द्र मोदी द्वारा 2013 में लायीं गई ज्योतिग्राम योजना ने विद्युत क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस योजना के द्वारा आज भी गुजरात के 18065 गवों को सतत चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अत विद्युत क्षेत्र में किए गए मोदी के प्रयासों ने गुजरात को सतत बिजली आपूर्ति में देश के सभी राज्यों में प्रथम पायदान पर ला कर खड़ा कर दिया

कृषि भारत की रीढ़ है। इसके विकास के आभाव में किसी भी राज्य के समुचित विकास की कल्पना नहींकी जा सकती है। नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र में भी गुजरात में अनेक विकास कार्य किए जिनमें सर्वप्रमुख कार्य नदियों को जोड़ना रहा। नरेन्द्र मोदी ने नदियों के संयोजन द्वारा गुजरात के कोने–कोने में सिचाई के लिए जल की व्यवस्था की। कृषि विश्वविद्यालयों का निर्माण, कृषि महोत्सव तथा मृदाकार्ड जैसे कार्यक्रमों ने गुजरात को विकास पथ पर अग्रसर किया

अतः कहा जा सकता है कि गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें गुजरात का विकास नहीं किया। जब शेष भारत भारी मुसीबतों से जूझ रहा था, तब मोदी का गुजरात इन सब से बचा हुआ था। गुजरात ने हर मोर्चे पर विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त की।

सन्दर्भ

आनन्द अरूण,2014 नमो वाणी, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन,

कामथ एम. वी 2013. वक्त की माँगः नरेन्द्र मोदी (प्रभात रंजन द्वारा अनुदित) नोएडा, विकास पब्लिशिंग,

कामथ एम.वी. ,एवं कालिन्दी रांदेरी,2014 विकास–शिल्पी नरेन्द्र मोदी, नई दिल्ली प्रभात प्रकाशन,

गौड अनिता, 2015 1000 मोदी प्रश्नोत्तरी, दिल्ली ससत्ज्ञ साहित्य प्रकाशन,

मकवाणा किशोर, 2016 कॉमन मैन नरेन्द्र मोदी, नई दिल्ली प्रभात प्रकाश,

मजूमदार सिद्धार्था, 2014 मोदीत्व, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन,

मुखोपाध्याय निलांजन, 2014 नरेन्द्र मोदी–एक शख्सियत एक दौर, चैन्नई वेस्टलैंड लि.,

मोदी नरेन्द्र, 2014 आँख ये धन्य है (अंजना संधीर द्वारा अनुदित) ,दिल्ली विकल्प प्रकाशन,

मोदी नरेन्द्र 2015 सामाजिक समरसता, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन

वर्मा सुरेशपाल 'जसाला' 2015 उत्कृष्ट व्यक्तित्व नरेन्द्र मोदी, दिल्ली पूनम प्रकाशन

शास्त्री ओ. पी. 2014 युवा हृदय सम्राट नरेन्द्र मोदी, मेरठ, धीरज प्रकाशन 2014 सरवनन, मोदी का विकासनामा, नई दिल्ली,